processing Zones schemes and allowing exporters of agriculture commodity to sell upto 50% of their production in the domestic tariff areas, extension of air freight subsidy to certain fruits, financial assistance to exporting units, market development and export promotion startegy adopted by the concerned export promotion authorities, participation in International trade fairs and Exhibitions, improving packaging, increasing awareness among the manufacturer-export ers etc. are all steps intended to improve and enlarge exports of these products.

Revision in policy on deemed exports

7357. SHRI SURESH KALMADI : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to revise its policy on deemed exports; and

(b) if so, what are the changes envisaged ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) Review of Exim Policy is a continuous process and changes are made therein as and when considered necessary in public interest.

इलैक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्यात

7358. **श्रीमती चंद्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश से इलैक्ट्रानिक उत्पादों के निर्यात में प्रतिशतता वार वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान देश द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में किन-किन इलैक्ट्रानिक उत्पादों के निर्यात से लाभ अर्जित किया है और गत वर्ष की तुलना में 1991–92 और 1992–93 के दौरान देश में कार्यरत एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इन एककों में कौन-कौन से मुख्य इलैक्ट्रानिक उपकरणों का उत्पादन किया जा रहा है ;

(ग) सरकार ने वर्ष 1993–94 और 1994–95 के वित्तीय बजट में इस उद्योग को उपलब्ध कराने हेतु क्रमशः कितनी-कितनी वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा है;

(घ) सरकार ने इलैक्ट्रानिक उत्पादों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय इलैक्ट्रानिक्स माल के निर्यात का मूल्य निम्नलिखित था:–

	(करोड़ रु० में)
1991–92	655
1992–93	615
1993–94 (अप्रैल–फरवरी)	879

कुल भारतीय निर्यातों में भारतीय इलैक्ट्रानिक्स निर्यातों का प्रतिशत जो अप्रैल-फरवरी, 1992–93 में 1.18 % था, वह अप्रैल––फरवरी, 1993–94 में बढ़कर 1.41 % हो गया ।

(स्रोत: डी०पी०सी०आई०एंड०एस०)

(ख) भारत विभिन्न देशों को अनेक किस्म के इलैक्ट्रानिक माल का निर्यात कर रहा है । उनको प्रमुखतः निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:–

उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स

रंगीन और श्वेत-श्याम टीवी, आडियो और वीडियो उत्पाद, खाली/रिकार्ड की

हुई केसेहस, इलैक्ट्रानिक घड़ियां, पीए उपस्कर आदि ।

ईलैक्ट्रानिक सघंटक

रंगीन पिक्चर ट्यूब, कैपेसिटर्स, फेराइटस, पीसी बोर्ड, आदि ।

दूर-संचार

टेलीकाम उपस्कर ईपीएबीएक्स, टेलीफोन उपस्कर, पुश बटन टेलीफोन, मोडेम कार्डस, संचार उपस्कर आदि ।

शक्तिकरण और औद्योगिक इलैक्ट्रानिक

आरिपलोस्कोप, नियंत्रण और मापक उपस्कर, एक्सरे उपस्कर, मेडिकल उपस्कर आदि ।

कम्प्यूटर हार्डवेयर

कम्प्यूटर प्रणाली, उप असेम्बलियां, और कम्प्यूटर प्रणालियों के पुर्जे, हैड-स्टैक असेम्बलियां, यूपीएस, एसएमपीएस, मदर बोर्डस, एड-आन कार्डस, मानीटर आदि ।

राज्यवार इकाईयों के ब्यौरे कलेंडर वर्ष आधार पर रखे जाते हैं और वर्ष 1991 तथा 1992 से संबंधित जानकारी निम्नलिखित है:-

सं०	नाम	इकाइयों की संख्या	
		1991	1992
1	आंध्र देश	150	144
2	असम	3	4
3	बिहार	17	17
4	चंडीगढ़	12	14
5	दिल्ली	323	312
6	गोआ	12	12
7	गुजरात	197	200
	काडला (एफटीजेड)	68	69
8	हरियाणा	1	1
9	हिमाचल प्रदेश	13	13
10	जम्मू और कश्मीर	4	4
11	कर्नाटक	268	276
12	केरल	73	79
	कोचीन (एफटीजेड)	3	3
13	मध्य प्रदेश	42	40
		697	711
14	महाराष्ट्र (एफ.टीजेड)	83	90
15	मणिपुर	1	—
16	मेघालय	1	1
17	उड़ीसा	10	11
18	पांडिचेरी	9	10
19	पंजाब	47	46
20	राजस्थान	64	72
21	सिक्किम	—	1
22	तमिलनाडु	256	273
	मद्रास (एफ टी जैड)	8	8
23	उत्तर प्रदेश	180	181
	नौएडा (एफटी जैड)	15	17
24	पश्चिम बंगाल	158	149
	फाल्टा (एफ. टी जैड)	1	2
25	दादरा-नागर हवेली	1	1
	योग :	2606	2640
	एफटी जोड :	111	121

(ग) वाणिज्य मंत्रालय के बजट में वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान इलैक्ट्रानिक्स और साफ्टवेयर के लिये व्यापक स्कीम "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिये सहायता" के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन के लिये किया गया बजटीय आवंटन निम्नलिखित है:-

(लाख रु० में)

1993-94 . .	47.63
1994-95 . .	37.22

(घ) और (ङ) वर्ष 1994–95 के लिये 1240 करोड़ रुपये के इलैक्ट्रानिक्स उत्पादों के निर्यात के लक्ष्य का प्रस्ताव है जो वर्ष 1993–94 के निष्पादन से 25 % अधिक है।

निर्यातकुत्री महिलाओं के संबंध में सर्वेक्षण

7359. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनदन जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात व्यवसाय में लगी महिला उद्यमियों की राज्य-वार संख्या और उनकी स्थिति के बारे में अभी तक कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात व्यवसाय में लगी महिला उद्यमियों की कुल संख्या कितनी है और आज की तारीख की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत निर्यातकुत्री महिलाओं की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार निर्यात व्यवसाय में लगी महिलाओं को इस व्यवसाय में विशेष प्रशिक्षण देने और उन्हें अन्य देशों में आयात संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में विशेष व्यवस्था करने का विचार रखती है ;

(घ) क्या मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, और गांधीधाम में महिलाओं के लिये विशेष निर्यात सूचना केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) व्यापार संबंधी जानकारी का संवितरण और निर्यात के लिये प्रशिक्षण एक सतत कार्य है।

Super-301 to be settled under GATT

7360. SHRI G. G. SWELL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Finance Minister has said that the question of imposition or non-imposition of the US trade law Super 301 will be settled under GATT;

(b) whether it is also a fact that the U.S.A. will have to get clearance from GATT before such imposition; and

(c) if not, whether U.S.A. can go ahead with its imposition and then leave it to the GATT mechanism to settle the question at its own pace ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) to (c) In response to a question Finance Minister had stated that the WTO provided a mechanism for resolving trade disputes amongst its members. Suspension of concessions by any members of the World Trade Organisation (WTO) against any other member without going through the multilateral dispute settlement procedure would not be consistent with the former's obligations under the WTO. If any member of the WTO acts inconsistently with its obligations, the affected members can have recourse to the dispute settlement procedures.

Support price for natural rubber

7361. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI : Will the Minister for COMMERCE be pleased to state whether Government have taken any decision not to provide any